When are you going to declare it a disturbed area?

यह बताइए?

श्री राजेश पायलट: मैडम्, जैसा मैंने कहा कि आज चिंता सबसे बड़ी है और कुछ इलाके में शांति आनी चाहिए।

श्री सिकन्दर बख्त: डिस्टर्ब्ड एरिया की बात बताइए। You said that you were contemplating. I want to know when you are coming out of your contemplation.

شری سکندر بخت: ڈسٹربڈ ایریا کی بات بتائیے

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोक सभा में कहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं। .....(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। .....(व्यवधान)

उपसभापति: एक मिनट, आप जवाब नहीं देने देते। सवाल-जवाब तो नहीं हो रहे हैं, न।

श्री राजेश पायलट: यह सरकार के बहुत सीरियस कंसीड्रेशन में है। बाकी डिपार्टमेंट के कमेंट्स आ गए हैं। We are going to consider it soon at the appropriate level and take a decision...*(Interruptions)*

श्री सिकन्दर बख्त: यह बाकी डिपार्टमेंट के कमेंट्स और उन्हें कंसीडर कर रहे हैं। अभी तक कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं आ रहा है। We are walking out of the House in protest. This is not the way.

شری سکندر بخت: یہ باقی ڈیپارٹمنٹ کے کمنٹس اور انہیں کنسیڈر کر رہے ہیں ابھی تک کوئی اسپیسفک جواب نہیں آرہا ہے۔

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

Refusal by S.B.I. and other financial institutions concessional rate of interest to sick P.S.U.S.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Madam, I want to draw the attention of the House, through you, towards the revival of the public sector undertakings...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, will you please have peace in the House?

SHRI MD. SALIM: Madam, the Government has been saying from time to time that they want to revive the sick industrial units. Now, I want to say, through this Special Mention, that there is a clear indication of discrimination against the sick public sector units. Madam, since 1992, the sick public sector units have been referred to the BIFR in accordance with the provision laid down in the Sick Companies Act. Now, when the BIFR gives some packages for the revival of these units, they involve some concessions, some reliefs, from the Government of India and the State Governments concerned who are the promoters...*(Interruptions)*

माथुर साहब, प्लीज, सिक यूनिट के बारे में कह रहा हूं। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मैं वाकआउट करके दोबारा आया हूं।

श्री मोहम्मद सलीम: नहीं-नहीं, माथुर साहब, आप रहिए और समर्थन कीजिए। राष्ट्रीय उद्योग जो बीमार पड़े हुए हैं, उसके बारे में कह रहा हूं जो देश की बीमारी का एक हिस्सा है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): माथुर जी, जब लौट आए हैं तो आने दीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, तो मैं यह कह रहा था कि जब बी०आई०एफ०आर० पैकेज डिक्लेयर करती है, तो जो पब्लिक सैक्टर के प्रमोटर्स है, गवर्नमेंट आफ इंडिया हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, वह कहते हैं कि उसमें कुछ कंसेशन होना चाहिए। बैंक के बारे में फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी कि उसको कुछ कंसेशन दिया जाए लौडिंग रेट के बारे में। और उसी तरह से ज़ो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं उन्हें भी कहा जाता है कि तुम कुछ करो और वह छंटनी और कुछ दूसरे पैकेज के बारे में, बे-पैकेज के बारे में कुछ-कुछ कंसेशन उनको भी छोड़ना पड़ता है। मैडम्, in fact, the managers sitting in the headquarters are issuing circulars to their subordinates in different parts of the country.

---

*Transliteration in Arabic Script.

लैंडिंग रेट में जो कंसेशन वर्किंग केपिटल जो बी॰आई॰एफ॰आर॰ के पैकेज के अनुसार बैंक को देना है, उसमें इंटरेस्ट रेट में जो कंसेशन होना चाहिए वह प्राईवेट सैक्टर को दिया जाए जो सिक यूनिट हैं। लेकिन जो पब्लिक सैक्टर यूनिट हैं, उसमें वह कंसेशन न दिया जाए। मेरे पास कम से कम एक बैंक का डौक्यूमैंट है। मैडम्, जो फाइनैंसियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, हमारे देश का पैसा और सरकार उसकी कस्टोडियन है। वह उसको रखे हुए हैं। सिक पब्लिक सैक्टर यूनिट की जो रिवाइवल का सवाल है, उसमें वह वर्किंग केपिटल, लौडिंग रेट, इंटरेस्ट रेट में जो कम है थोड़ा कंशेसन हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार खास करके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वह यह नहीं चाहती कि जैसे भी हो वह सेमिनार में कहे, जैसी भी वह पर्लियामेंट में कहे कि हम रिवाइवल चाहते हैं सिक यूनट का। लेकिन वह डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं प्राईवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के अंदर। यह निजीकरण का भूत चढ़ा हुआ है चाहे वह प्राईवेट सैक्टर के बारे में हो। वह सरकार की नीति का सवाल है। लेकिन यहां जब सरकार बैंक को यह कह रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं, सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं, क्या यह सरकार की पौलिसी है कि बीमार उद्योग को सही करने के लिए जो निजी उद्योग हैं और जो राष्ट्रीय उद्योग हैं, इसमें फर्क करें। अगर वह नहीं करें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह बात करेंगे कि बैंक के ऐसे कौन से आला अफसर हैं जो ऐसे सर्क्यूलर इश्यू करते हैं। बी॰आई॰एफ॰आर॰ का स्पैसिपिक पैकेज है। बी॰आई॰एस॰आर॰ ने जब पैकेज दिया रिवाईवल का तो ये बैंक कह रहे हैं कि हम आपको लौडिंग रेट में कंसेशन नहीं दे सकते हैं। उन यूनिट्स को कंसेशन क्यों नहीं दे सकते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटर है, प्रमोटर है, स्टेट गवर्नमेंट्स प्रमोटर्स है। अगरचे आर॰बी॰आई॰ गाईडलाइंस में भी कहा गया है कि प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो। जो सिक यूनिट्स है, वीक यूनिट्स है, उनको रिवाईव करने के लिए आपको ये कंसेशन देना पड़ेगा।

तो मैं चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि जो बीमार उद्योग हैं, चाहे वे पब्लिक सैक्टर में हो या प्राइवेट सैक्टर में हों, उनके रिवाईवल के बारे में आर॰बी॰आई॰ की जो स्टिपुलेटेड गाईडलाइंस है, बी॰आई॰एफ॰आर॰ की जो डायरेक्शंस हैं, जो अफ्सर उनको वॉयलेट कर रहे हैं, क्या वे फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोलेज के तहत वायलेट कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्या वे ऐसा आर्डर इशू करेंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और बी॰आई॰एफ॰आर॰ पैकेज के अनुसार निजी उद्योग की तरह राष्ट्रीय उद्योगों को भी लौडिंग रेट में कंसेशन मिलना चाहिए।

*شری محمّد سلیم "مغربی بنگال": ماتھر صاحب بیٹھئے۔ "سک یونٹ" کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں۔ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں۔

شری جگدیش پرساد ماتھر: میں واک آؤٹ کر کے دوبارہ آیا ہوں۔

شری محمّد سلیم: نہیں نہیں ماتھر صاحب آپ رہیے اور سمرتھن کریے۔ راشٹریہ ادیوگ جو بیمار پڑے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جو دیش کی بیماری کا ایک حصّہ ہیں۔

شری چترانن مشر: ماتھر جی جب لوٹ آئے ہیں تو آنے دیجیے۔

شری محمّد سلیم: میڈم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بی۔ آئی۔ ایف۔ آر۔ پیکیج ڈکلیئر کرتی ہے تو جب پبلک سیکٹر میں پروموٹر ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ہو اور اسٹیٹ گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کنسیشن ہونا چاہیے بینک کے بارے میں۔ فائینینشیل انسٹی ٹیوشن کے بارے میں بھی کہ اس کو کچھ کنسیشن دیا جائے لینڈنگ ریٹ کے بارے میں اور اسی طرح سے جو لبرس ہیں۔ ورکرس ہیں انھیں بھی کہا جاتا ہے کہ تم کچھ کرو تو وہ

*Transliteration in Arabic Script.

چھٹنی اور کچھ دوسرے پیکج کے بارے میں۔
ہے۔ پیکیج کے بارے میں کچھ کنسیشن
ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ میڈم ابھی جو
لینڈنگ ریٹ میں جو کنسیشن ورکنگ
کیپٹل جو بی۔ آئی۔ ایف۔ آر۔ کے پیکیج کے
انوسار بنک کو دینا ہے اس میں انٹرسٹ
ریٹ میں جو کنسیشن ہونا چاہیے وہ پرائیویٹ
سیکٹر کو دیا جائے میرے پاس کم سے کم
ایک بنک کا ڈوکومنٹ ہے۔ میڈم جو
فائننشیل انسٹی ٹیوشنس ہیں جو نیشنلائزڈ
بنک ہیں ہمارے دیش کا پیسہ اور سرکار اس
کی کسٹوڈین ہے وہ اس کو رکھے ہوئے ہے۔
"سیک پبلک سیکٹر یونٹ" کی جو ریوائیول
کا سوال ہے اس میں وہ ورکنگ کیپیٹل۔
لینڈنگ ریٹ انٹرسٹ ریٹ میں جو کم ہے
تھوڑا کنسیشن ہو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
لیکن اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ سرکار
خاص کر کے جو فائننس منسٹری ہے وہ یہ
نہیں چاہتی کہ جیسے بھی ہو وہ سیمینار میں کہے۔
جیسے بھی وہ پارلیمنٹ میں کہے کہ ہم ریوائیول
چاہتے ہیں سیک یونٹ کا لیکن وہ ڈسکریمینیشن
کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک
سیکٹر کے اندر۔ یہ نجی کرن کا بھوت چڑھا
ہوا ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بارے
میں ہو، وہ سرکار کی نیتی کا سوال ہے۔ لیکن
یہاں جب سرکار بنک کو یہ کہہ رہی ہے۔ میں
یہ پوچھنا چاہتا ہوں سدن کے نیتا یہاں
بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ سرکار کی پالیسی ہے کہ
بیمار ادیوگ کو صحیح کرنے کے لیے جو نجی ادیوگ
ہیں اور جو راشٹریہ ادیوگ ہیں اس میں فرق
کریں۔ اگر وہ نہیں کریں تو میں یہ جاننا
چاہتا ہوں کہ کیا وہ فائننس منسٹری سے یہ
بات کریں گے کہ بنک کے ایسے کون سے
اعلیٰ افسر ہیں جو ایسے سرکولر ایشو کرتے ہیں۔

*Transliteration in Arabic Script.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, this is a total violation of the laws of the land. It is not a question of mercy that the public sector employees are asking for. These are the guidelines of the Reserve Bank of India. The guidelines of the Reserve Bank of India are being flouted. The BIFR has issued a directive that the concessions should be extended to the public sector as well as private sector units. Here is a letter of the Deputy Managing Director of the State Bank of India. In this letter, he specifically says that the directives of the BIFR are to be flouted and the banks should not agree to extend any concessions so far as interest rates are concerned. This is not about the Bharat Brakes and Valves Limited only. I have personal experience regarding the Tyre Corporation of India also. The State Bank of India, the Industrial Development Bank of India, etc., are violating all the laws of the land. How is it possible? Who are encouraging this? They are not coming out. There are no circulars. They are only saying all this orally that the concessions should be given to the private units only. I hope the Leader of the House is listening to me ...(*interruptions*)... should I shout more?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am listening to you. Don't worry.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Please convey this. We want a specific

assurance. If the Government wants to kill the PSUs– let them come out clearly, specifically, instead of doing all this exercise for the last two years through the BIFR. The Unions are coming, the units are coming and the managements are coming. All this ruckus is going on and the Governemnt refueses to act as a promoter and ask the banks not to extend any concessions. What is all this *tamasha*: ...(*interruptions*)... Madam, should I read out the circular? The circular is here. I will just read out the letter of the Deputy Managing Director of the State Bank of India. He writes:

> "...We particularly draw your attention to para 7(c) where the Bench has held the view that RBI guidelines are applicable to sick units regardless of whether they are public or private sector units..."

THE DEPUTY CHAIRMAN: What are you reading?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The letter of the Deputy Managing Director.

SHRI MD. SALIM: Can't he read it out? We are ready to authenticate it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't read it out? ...(*interruptions*)... No ...(*interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What is your problem?..(*interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. Just one minute. Mr. Dipankar Mukherjee, just a minute. I am trying to explain to you what the rules and procedures of this House are. A newspaper report, which is a public report, can be referred to by the Members. You say that this is a document, an internal document circulated among the bank people. Now, how can a Member or myself be satisfied that this is the actual document? What is the guarantee?

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, a Member can quote from any document, classified or otherwise, if he deems it fit provided he is prepared to authenticate it and lay it on the table of the House. The hon. Member is prepared to authenticate it and lay it on the table of the House. Therefore, there can be no objection.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would not allow him to lay it on the table. But I definitely would like him to authenticate it and show it to me what it is because I don't know what he is reading out.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I have already read it out. The State Bank of India says--this is the directive about the Bharat Brakes & Valves Limited--that in spite of the directive from the BIFR, the instruction is that the concession which has to be extended to sick private units cannot be applicable to public sector units, and so, this is the information to be told to the BIFR. Madam, this is the crux of the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is the content?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: This is the content. And I express myself that in the present case, I have information that the SBI has not given concessional rates of interest. I can cite 50 cases like that.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, may I make a point? Madam, if the Bank is to lend, it should be lending either to a public sector unit or a private sector unit in a non-discriminatory way. What is applicable to private sector units should also be applicable to the PSUs. He has levelled a serious charge, substantiated by documentary evidence that the PSUs are being discriminated against by the nationalised banks. And if he charge is true--I am not aware of it--the Government should react because these PSUs were built up with the blood and toil of the people of India, and they cannot be allowed to be starved to death.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI S.B. CHAVAN): May, I clarify the position? Though this is not my subject, still I can take up this matter with the hon. Finance Minister. And if it is a fact that there is a clear-cut discrimination between the pulic sector units and the private sector units which they have financed, in fact, the Government will have to interfere in the matter and see that the PSUs are not discriminated against.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please show that document to me in my Chamber; not now but later on.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Yes, Madam.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: महोदया, मेरे दल की

भी नीति के अनुसार प्राइवेट बैंक हों लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ हैं उन का डिस्क्रिमिनेशन किया जाउ, यह बिलकुल गलत है और मैं गृह मंत्री महोदया का विश्वास करता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर फाइनेंस मिनिस्टर इस पर इंटरफियर करके मामले को ठीक करेंगे।

उपसभापति: माथुर साहब, आप का नाम मैंने लिया था किसी और सिलसिले में।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, Mathurji is all the time standing. Whenever you call him, he will speak, There is no difficulty.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I called his name regarding terrorism. but he was hijacked to banking.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: अब आप अपनी मंशा बताइए मुझे किसलिए बुलाया था।

उपसभापति: मैंने आप को बुलाया था जो लिस्ट में स्पेशल मैंशन है।...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: माइक के पास से बोलने की मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है।...**(व्यवधान)** आपने कल चाय नहीं पिलाई ठंडा पिलाया, इसलिए बैठ गया...

श्री चतुरानन मिश्र: इतनी चीनी खा ली है कि गला बैठ गया।

Pakistan's Hand in Increase in Terrorism in Kashmir

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, क्लिंटन ऐडमिनिस्ट्रेशन और उनकी सरकार का दोगला रवैया है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के संबंध में, उस को मैं उजागर करना चाहता हूं कि किस प्रकार से वह अपनी स्थिति पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में बदलते रहे हैं।

महोदया, समाचार छपा है, किसी और का नहीं, उन्हीं के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। उनका स्टेटमेंट कहता है कि पाकिस्तान में अभी भी कैम्प्स चल रहे है, ट्रेनिंग हो रही है और हिन्दुस्तान में उन टैरोरिस्टों को भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान केवल अपनी लोगों को ही नहीं भेज रहा है, बल्कि इजिप्ट, अल्जीरिया अफगानिस्तान, सूडान, मिडिल-ईस्ट के लोगों को भी ट्रेन करके यहां पर भेज रहा है। सब जानते हैं कि वहां गृह युद्ध के समय बहुत से गैर अफगानिस्तानीज वहां भेजे गये थे। वे प्रोफेशनल थे, पेशेवर थे, क्रिमिनल थे। उन सब को यह देश पाकिस्तान के माध्यम से कश्मीर में विशेषत: और उससे पूर्व शायद यहां पंजाब में भेजते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले समाचार छपा था कि अमेरीका पाकिस्तान को देख रहा है कि पाकिस्तान को टैरोरिस्ट स्टेट घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन बाद में हुआ कि उन्होंने उसका नाम वहां से निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि शायद क्लिंटन महोदय को पता था कि इस प्रकार की रिपोर्ट आने वाली है। उन्होंने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान को टेरोरिस्ट स्टेट की लिस्ट में रखने से वापस ले लिया। मैं भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं और क्लिंटन महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि अमेरिका की दोहरी नीति से भारत का एक-एक व्यक्ति परिचित हो गया है और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को टेरोरिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान हर इन्टरनेशनल फोरम का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, हमें भी उसी प्रकार से, यह बात जरूर है कि उनके रवैये में और हमारे रवैये में अंतर है, हमारा देश सांस्कृतिक दृष्टि से संयमी देश है लेकिन संयम का अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग यह समझें कि यह बुजदिल है, हमें हर इन्टरनेशनल फोरम पर प्रयत्न करके यह करना चाहिए कि पाकिस्तान को टेरोरिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता जब कि उनका स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि पाकिस्तान देशी विदेशी सारे देशों के टेरोरिस्टों को हिन्दुस्तान के अंदर भेज रहा है तो मैं समझता हूं गृह मंत्री महोदय यहां बैठे हैं और सारा सदन इससे सहमत होगा कि पाकिस्तान को टेरोरिस्ट स्टेट घोषित किया जाना चाहिए।

BOMB BLAST AND CYCLONE IN GOA

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): Madam, yesterday there was an unfortunate incident of a bomb blast at Margao. The intensity of the explosion was so powerful that it created a crater of five inches in the concrete floor and the explosion was heard up to a radius of about two kilometres in Margao. The police report says that the explosive contained RDX.

Madam, after the Bombay blast, I have repeatedly raised it in the House that RDX was landed in Goa also by the accomplices of Memon, and there were reports in the press that some politicians in Goa have links with Memon. I requested the hon. Home Minister to investigate this. It is also reported that at least 1,000 kg. of RDX is hidden in Goa. We have about 10,000 Kashmiris in Goa, and these people are not being acreened. There is every possibility that the agents of the ISI of Pakistan are taking shelter in Goa.

It is a known fact that Goa is a haven for fugitives. Charles Sobhraj was